

न्याय तक पहुँच के अधिकार से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

■ संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार): अनुच्छेद 14 वधि के समक्ष समता और वधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या न्याय तक पहुँच के अधिकार को शामिल करते हुए की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी व्यक्तियों को बर्ना किसी भेदभाव के वधिक संरक्षण पाने का समान अवसर मिले।
- अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार): अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी शक्तियों के लिये न्यायिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होती है।
 - अनुच्छेद 39A (नःशुल्क वधिक सहायता): अनुच्छेद 39A नःशुल्क वधिक सहायता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न होना पड़े।
 - इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना है, यह विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों पर केंद्रित है।
 - अनुच्छेद 32 और 226: अनुच्छेद 32 और 226 पीढ़ति पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर न्याय तक पहुँच के अपने अधिकार को लागू करने की अनुमति देता है।

■ वधिक ढाँचा:

- वधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने समाज के वंचित वर्गों को मुफ्त वधिक सहायता प्रदान करने के लिये नालसा की स्थापना की।
 - अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पात्र समूहों में महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, वकिलांग व्यक्ति और नमिन आय वाले व्यक्ति शामिल हैं, जससे कमज़ोर आबादी के लिये कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
- लोक अदालतें अधिनियम के अंतर्गत त्वरति एवं सुलभ विवाद समाधान उपलब्ध कराती हैं।
 - टेली-लॉ हाशए पर स्थति समुदायों को वधिक परामर्श प्रदान करता है, जबकि ई-लोक अदालतें उन लोगों के लिये पहुँच सुनिश्चित करती हैं जो भौतिक सुनवाई में भाग लेने में असमर्थ हैं।
- लोकहति वाद (PIL):
 - लोकहति वाद से सुने जाने के अधिकार (locus standi) का वस्तितार हुआ, जससे न केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों को अपति जनहितैषी व्यक्तियों या संगठनों को भी अधिकारों को प्रवर्तित करने के हेतु मामले दर्ज कराने की सुवधि मिली।
 - उदाहरण: 1987 दल्लि में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहति वाद था।

1987 दल्लि में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहति वाद था।

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका में मामलों के लगातार लंबति रहने के मुद्दे पर चर्चा कीजिये और इसे हल करने के लिये पर्याप्त उपायों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

1987 दल्लि में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहति वाद था।

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2019)

1. भारत के संवधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया।
2. भारत के संवधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को नःशुल्क एवं सक्षम वधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश भर में वधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य वधिक सेवा प्राधिकरणों को नरिदेश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

प्रश्न. निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निशुल्क कानूनी सहायता के प्रत्येक मामले में राष्ट्रीय वधिविसेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिये। (2023)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/limits-to-the-right-to-access-justice>

